

Daily Current Affairs

Date : 02 May, 2026



अनुक्रमणिका

| क्र. सं. | टॉपिक का नाम |
|----------|---|
| 1. | राजस्थान ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता (RECSBC) |
| 2. | 'विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम' के लिए MoU |
| 3. | इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य - राजस्थान |
| 4. | 'अष्टम पोषण पखवाड़ा' में राजस्थान देश भर में अव्वल |
| 5. | न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. 'स्त्री शक्ति समृद्धि' अभियान 2. देश के सबसे विशाल गंगा मंदिर का पुनरोद्धार 3. तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप - 2027 का मेजबान : राजस्थान 4. राजस्थान साहित्यकार आर्थिक सहयोग - 2025-2026 5. राजस्थान में 'जनगणना - 2027' का औपचारिक शुभारंभ |
| 6. | सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च |
| 7. | यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) |
| 8. | प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा |
| 9. | नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य-देखभाल पहलें |
| 10. | मिशन सक्षम (Mission SAKSHAM) |
| 11. | महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (IS-PCMR) |
| 12. | जमैका (राजधानी: किंग्स्टन) |
| 13. | नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित |
| 14. | व्हिटली पुरस्कार |

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता (RECSBC)



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) द्वारा राजस्थान ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता (RECSBC) और नियम का प्रारूप जारी कर सुझाव आमंत्रित किये गये।

राजस्थान ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता (RECSBC)



ऊर्जा दक्ष भवन • सस्टेनेबल भविष्य • सशक्त राजस्थान

मुख्य उद्देश्य

- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना
- जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना
- सस्टेनेबल निर्माण सामग्री को बढ़ावा देना
- पर्यावरण अनुकूल और स्वस्थ भवन सुनिश्चित करना
- अनुपालन एवं प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाना

हमारे
मूल सिद्धांत



सततता
पर्यावरण के प्रति
जिम्मेदारी



समावेशन
सभी के लिए सुरक्षित
और आरामदायक भवन



दक्षता
कम संसाधन में
अधिकतम परिणाम



अनुपालन
मानकों एवं नियमों
का सरल पालन



सहयोग
सरकार, उद्योग और
नागरिकों की साझेदारी



मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता के न्यूनतम मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए 'ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता (RECSBC)' जारी की गई है।

--:2:--

- इसी क्रम में, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता (RECSBC) लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- यह नई संहिता वर्तमान में अधिसूचित एवं लागू 'राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (RECBC)' को प्रतिस्थापित करेगी।
- प्रस्तावित संहिता उन व्यावसायिक भवनों पर लागू होगी, जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवॉट या उससे अधिक अथवा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 120 किलोवॉट या उससे अधिक अथवा बिल्टअप एरिया 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक होगा।
- वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं पार्किंग को 20 प्रतिशत एवं न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को अनुबंधित माँग का 4 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, कोड में "RECSBC Plus" भवनों के लिए 5 प्रतिशत और "Super RECSBC" भवनों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिल्टअप एरिया रेशियो (BAR) का प्रावधान किया गया है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL)

- गठन : अगस्त, 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी (REDA) और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSPCL) के विलय से।
- कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत।
- RRECL का उद्देश्य राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है।

'विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम' के लिए MoU



चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार ने युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 'विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम' की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के लिए 1 मई, 2026 को जयपुर में महत्त्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।



राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

विदेशी भाषा का ज्ञान, राजस्थानी युवाओं को वैश्विक अवसरों की नई उड़ान

सीखेंगे जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी और स्पेनिश

विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम
के लिए
एम.ओ.यू. हस्ताक्षर समारोह

1 मई 2026, प्रातः 10:30 बजे • बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर

राजस्थान सरकार
का
इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
और
नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन
के साथ एम.ओ.यू.

गरिमामयी उपस्थिति

श्री धर्मेन्द्र प्रधान
माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

डॉ. प्रेम चंद बैरवा
माननीय उप मुख्यमंत्री व उच्च एवं
तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार

श्री जयंत चौधरी
माननीय कौशल विकास एवं
उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार

श्री कृष्ण कुमार के.के. विश्नोई
माननीय राज्य मंत्री, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग
राजस्थान सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग • कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग



मुख्य बिन्दु:

- इंग्लिश एंव फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद : राजस्थान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी (EFLU), हैदराबाद के बीच MoU, जिसके तहत विद्यार्थियों को फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन भाषाएँ सिखाई जाएंगी।

Daily Current Affairs

Date : 02 May, 2026



- **नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) :** जयपुर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) की स्थापना करने के लिए NSDC और राजस्थान सरकार के बीच समझौता। यह केंद्र अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं को वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण, भाषा दक्षता और माइग्रेशन सहायता प्रदान करेगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **'नेशनल एंटरप्रेन्योर्स एम्पावरमेंट ड्राइव' (NEED):** केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 1 मई, 2026 से जयपुर से 'नेशनल एंटरप्रेन्योर्स एम्पावरमेंट ड्राइव' (NEED) की शुरुआत की गई। यह पहल ग्रामीण उद्यमिता को मज़बूत करने और भारत को कुशल प्रतिभा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:5:--

इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य - राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गाँधी नगर (जयपुर) में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के कार्यालय और प्रशासनिक परिसर का उद्घाटन किया।



मुख्य बिन्दु:

- उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति और बोर्ड को मान्यता देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड को वैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु राजस्थान विधानसभा द्वारा वर्ष 2018 में 'राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2018' पारित किया गया था। तत्पश्चात 01 मई, 2025 को इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा गठित इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित छह सदस्य होंगे।

--6--

संरचना:

- **अध्यक्ष :** आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव।
- **सदस्य:**
 - हेमंत सेठिया।
 - गोविंदलाल सैनी।
 - कुलदीप वर्मा।
 - हरिसिंह बूमरा।
 - SS पाटोदिया।
- **इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति :** इलेक्ट्रोपैथी एक अपेक्षाकृत नई चिकित्सा पद्धति है, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की श्रेणी में मान्यता प्राप्त है।
- इस चिकित्सा पद्धति की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1865 में एक इतालवी सशस्त्र बल अधिकारी डॉ. काउंट सीज़र मैटी द्वारा की गई थी।
- यह चिकित्सा प्रणाली पूर्णतः हर्बल (वनस्पति) पर आधारित है, जो वनस्पति-जगत से प्राप्त औषधीय गुणों पर आधारित है।
- इन औषधीय गुणों को कोहोबेशन (जिसकी प्रक्रिया आयुर्वेद में अर्क निकालने जैसी होती है) के माध्यम से निकाला जाता है और नियंत्रित अनुपात में डिस्टिल्ड एवं डिनैचर्ड अल्कोहल युक्त जल और स्पैजेरिक एसेंस के साथ मिलाया जाता है।
- इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का पूरा सिद्धांत मानव शरीर में दो महत्वपूर्ण द्रवों — रक्त (Blood) और लसीका (Lymph) के संतुलन पर आधारित है।
- **विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस :** प्रति वर्ष 11 जनवरी को इलेक्ट्रोपैथी पद्धति के जनक डॉ. काउंट सीज़र मैटी के जन्म दिवस पर।

'अष्टम पोषण पखवाड़ा' में राजस्थान देश भर में अट्वल

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'अष्टम पोषण पखवाड़ा' (9 से 23 अप्रैल, 2026) में राजस्थान ने देशभर में सर्वाधिक गतिविधियाँ आयोजित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।



मुख्य बिन्दु:

- रिकॉर्ड गतिविधियाँ :** अभियान के दौरान राजस्थान ने कुल 45 लाख 37 हजार 229 गतिविधियाँ संपन्न कीं।
- व्यापक भागीदारी :** प्रदेश के 41 जिलों के 62,139 आँगनबाड़ी केंद्रों पर इन गतिविधियों का सफल संचालन किया गया।
- मुख्य विषय (Theme) :** इस बार का मुख्य फोकस "जीवन के प्रथम 06 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास" था। इसके साथ ही बच्चों में 'स्क्रीन टाइम' कम करने और खेल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'नो स्क्रीन आवर' और 'फैमिली प्ले टाइम' अभियान चलाए गए।

--8--

Daily Current Affairs

Date : 02 May, 2026



- **सफलता प्रतिशत** : राजस्थान ने 112.33 प्रतिशत उपलब्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- **प्रमुख कार्यक्रम** : पखवाड़े के दौरान "पोषण की कहानी: दादी-नानी की जुबानी", स्वस्थ भोजन बनाम जंक फूड के प्रति जागरूकता, और गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए गए।
- **खेल आधारित शिक्षा** : 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खेल के माध्यम रोचक ढंग से शिक्षा देकर उनके संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया गया। इसके लिए आँगनबाड़ी केंद्रों पर DIY खिलौना कार्यशाला, योग, नृत्य और कहानी सत्र आयोजित किए गए।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

पोषण अभियान:

- कुपोषण की समस्या के निराकरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा झुंझुनू से देश भर में 8 मार्च, 2018 को 'पोषण अभियान' की शुरुआत की गई।
- कुपोषण संबंधी समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य** : समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी कमियों में सुधार करना।

पोषण ट्रैकर ऐप:

- 'पोषण ट्रैकर' एक मोबाइल आधारित ऐप्लिकेशन है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के माध्यम से शुरू किया गया।
- इस ऐप द्वारा बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, कम वजन की व्यापकता की सशक्त पहचान और पोषण सेवा वितरण की ट्रैकिंग की जा रही है।
- साथ ही इस ऐप के माध्यम से आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवाओं के कुशल वितरण में सहायता एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है।

--9--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

| क्र. सं. | न्यूज़ |
|----------|--|
| 1. | <p>'स्त्री शक्ति समृद्धि' अभियान</p> <ul style="list-style-type: none">■ कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड और दैनिक भास्कर समूह ने महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'स्त्री शक्ति समृद्धि' अभियान शुरू किया।■ इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को म्यूचुअल फंड निवेश की बुनियादी विशेषताओं, वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की रणनीतियों के बारे में शिक्षित करना है। |
| 2. | <p>देश के सबसे विशाल गंगा मंदिर का पुनरोद्धार</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, भरतपुर स्थित देश के सबसे विशाल गंगा मंदिर का 90 साल बाद पुनरुद्धार कार्य शुरू किया गया। यह मंदिर अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बनने में 92 वर्ष का समय लगा था।■ निर्माण काल : मंदिर की नींव महाराजा बलवंत सिंह ने वर्ष 1845 में रखी थी, जो वर्ष 1937 में बनकर तैयार हुआ।■ शैली : मंदिर की वास्तुकला में राजपूत, मुगल और दक्षिण भारतीय (द्रविड़) शैलियों का संगम देखने को मिलता है। |
| 3. | <p>तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप - 2027 का मेजबान : राजस्थान</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : 18 से 21 मार्च, 2027 तक।■ आयोजन स्थल : सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेड़ी बाड़ी (झुंझुनूं)■ आयोजक : पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (PTFI) |

| | |
|----|--|
| 4. | <p>राजस्थान साहित्यकार आर्थिक सहयोग - 2025-2026</p> <ul style="list-style-type: none">वर्ष 2025-2026 में राजस्थान साहित्यकार आर्थिक सहयोग के तहत कुल 5 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया।साहित्यकार : राजाराम भादू (जयपुर), ब्रह्मानन्द बाबा (चित्तौड़गढ़), पूर्णिमा मित्रा (बीकानेर), रामस्वरूप किसान (हनुमानगढ़), गोविन्द जोशी (बीकानेर)।नोट : साहित्यिक पत्र-पत्रिका सहयोग योजना में कुल 9 पत्रिकाओं को सहयोग प्रदान किया गया। |
| 5. | <p>राजस्थान में 'जनगणना - 2027' का औपचारिक शुभारंभ</p> <ul style="list-style-type: none">1 मई, 2026 को राजस्थान में 'जनगणना - 2027' की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा लोक भवन (जयपुर) में स्व-गणना के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही राज्य भर में जनगणना गतिविधियों का पहला चरण शुरू हो गया।उल्लेखनीय है कि यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा का संग्रह डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, नागरिकों को एक सुरक्षित वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है। |

SERVICES

भूगोल एवं भू-विज्ञान

सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पूरे भारत में मोबाइल उपकरणों पर दिखाई देने वाली "अत्यंत गंभीर चेतावनी" अधिसूचना देश की आपदा तैयारी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है।



मुख्य बिन्दु:

- मोबाइल फोन पर यह आपातकालीन चेतावनी सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत बाढ़, भूकंप और औद्योगिक खतरों जैसी गंभीर स्थितियों के दौरान वास्तविक समय में चेतावनी देने में सक्षम एक मजबूत एनडीएमए चेतावनी प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है।

संस्थागत ढाँचा

- संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से जीवन रक्षक सूचनाओं के समय पर प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल-आधारित आपदा संचार प्रणालियों को सक्रिय रूप से बढ़ाया है।
- इस पहल के मूल में एकीकृत चेतावनी प्रणाली (SACHET) है, जिसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संस्थान, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) द्वारा विकसित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर निर्मित।
- सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत
- SMS के माध्यम से भौगोलिक रूप से लक्षित अलर्ट सक्षम करता है।

सैशे क्या होता है?

- SACHET (सिस्टम फॉर एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंड होलिस्टिक इमरजेंसी ट्रांसमिशन) भारत की एकीकृत चेतावनी प्रणाली है, जो अधिकारियों को SMS और सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मोबाइल उपयोगकर्ताओं को भौगोलिक रूप से लक्षित आपदा चेतावनियाँ सीधे भेजने में सक्षम बनाती है।
- इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत टेलीमैटिक्स विकास केंद्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से वास्तविक समय में आपातकालीन संचार को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है।

आर्थिक घटनाक्रम

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

चर्चा में क्यों?

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए।



मुख्य बिन्दु:

UPI

- **प्रारंभ:** अप्रैल 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा। यह भुगतान प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक पर्यवेक्षण में कार्य करती है।
- **अर्थ:** UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप से जोड़ती है। यह विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं को एक साथ लाकर पैसे का आसानी से ट्रांसफर और व्यापारियों को भुगतान एक ही प्लेटफॉर्म पर संभव बनाती है।

UPI की प्रमुख उपलब्धियाँ

- **वार्षिक लेनदेन की मात्रा (संख्या):** वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ हो गई।
- **UPI से जुड़े बैंक:** वित्त वर्ष 2016-17 में 44 बैंकों से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 तक 703 बैंक हो गए हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट्स बैंक और सहकारी बैंक, आदि शामिल हैं।
- **वैश्विक पहुँच:** वर्ष 2024 में विश्व के लगभग 49% रियल-टाइम भुगतान लेनदेन UPI के जरिए हुए। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी की है।
- यह कई देशों में संचालित हो चुका है, जैसे— संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, कतर। इससे इसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

- यह भारत में रिटेल भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक शीर्ष संगठन है।
- **संस्थापक:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा स्थापित।
- **विधिक ढाँचा:** भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत।
- **स्वरूप:** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी।
- **NPCI द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख उत्पाद:**
 - तत्काल भुगतान सेवा (IMPS),
 - नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH),
 - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI),
 - RuPay (रुपे),
 - आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) आदि।

प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा

चर्चा में क्यों?

- प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का उपयोग भारत के पहले ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाएगा। इससे समुद्र में चलने वाले जहाजों को ईंधन मिलेगा।



मुख्य बिन्दु:

प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा

- यह सूखे और लवणता सहिष्णु फलीदार पादप है। यह विश्व की सबसे प्रमुख आक्रामक प्रजातियों में से एक है।
- यह मैक्सिको की देशज प्रजाति है।

पारिस्थितिकी पर प्रभाव:

- यह गहरी जड़ों वाला (फ्रीटोफाइट) पादप है, जो भूमिगत जल स्तर के नीचे के क्षेत्र से पानी खींचता है। इससे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और हाइड्रोलॉजिकल सूखा और अधिक गंभीर हो सकता है।
- यह देशज पौधों की विविधता को कम करता है, जिससे पादप विविधता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
- **IUCN लाल सूची स्थिति:** लिस्ट कंसर्न।

समाजशास्त्र

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य-देखभाल पहलें



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने '10वें राष्ट्रीय नवाचार और समावेशन शिखर सम्मेलन' में स्वास्थ्य-देखभाल के क्षेत्र में कई पहलों की शुरुआत की।



मुख्य बिन्दु:

शुरू की गई नई पहलें

- **स्वस्थ भारत पोर्टल:** यह वन-स्टॉप एकीकृत मंच है। इसे कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही डिजिटल इंटरफेस पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप है और आभा (ABHA - आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) के साथ एकीकृत होता है।
- **जननी पोर्टल (JANANI: जर्नी ऑफ़ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर):** यह प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य डेटा को ट्रैक करता है और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जीवन-चक्र दृष्टिकोण को अपनाता है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) 2.0 तथा बच्चों एवं किशोरों में मधुमेह पर मार्गदर्शन दस्तावेज़:** ये बच्चों में नई बीमारियों और गैर-संचारी रोगों सहित बाल स्वास्थ्य-देखभाल की बदलती जरूरतों का समाधान करने वाले अद्यतन दिशा-निर्देश 2013 में हैं।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

मिशन सक्षम (Mission SAKSHAM)

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक मिशन-मोड, क्षेत्रक-व्यापी, अखिल भारतीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण पहल, मिशन सक्षम की शुरुआत की है।



मुख्य बिन्दु:

- UCBs सहकारी बैंकों का एक उपसमूह हैं जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

मिशन सक्षम

- इसका उद्देश्य UCBs के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम (व्यक्तिगत रूप से और ई-लर्निंग पाठ्यक्रम) आयोजित करना है।
- इसमें बोर्ड के सदस्यों; वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम, अनुपालन और ऑडिट कार्यों के प्रमुखों तथा IT कार्यों व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित विभिन्न लक्षित समूहों को शामिल किया गया है।
- इसे UCBs के अम्ब्रेला संगठन और राष्ट्रीय / राज्य सहकारी संघों के परामर्श से तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (IS-PCMR)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 58 कंपनियों को पात्र भागीदार के रूप में मंजूरी दी है।



मुख्य बिन्दु: IS-PCMR

- इस योजना को अक्टूबर 2025 में अधिसूचित किया गया था। यह राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल मिशन (NCMM) का एक भाग है।
- संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय खान मंत्रालय
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करना और स्वच्छ ऊर्जा एवं उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है।
- योजनावधि: 6 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक)।
- पात्र अपशिष्ट: ई-अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरी स्कैप, तथा ई-अपशिष्ट व स्कैप के अलावा अन्य स्कैप (जैसे- पुराने हो चुके वाहनों में इस्तेमाल होने वाले कैटेलिटिक कन्वर्टर्स)।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

जमैका (राजधानी: किंग्स्टन)

चर्चा में क्यों?

- भारत ने जमैका को अपनी प्रमुख 'आरोग्य मैत्री' पोर्टेबल स्वास्थ्य-देखभाल सेवा अवसंरचना प्रदान की है।



--:20:--

Daily Current Affairs

Date : 02 May, 2026



मुख्य बिन्दु:

- 'आरोग्य मैत्री' परियोजना एक मानवीय पहल है जो वैश्विक स्वास्थ्य-देखभाल और आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरी करती है।
- **भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एवं मैत्री (BHISHM):** यह आरोग्य मैत्री पहल का हिस्सा है, जिसमें छोटे, पोर्टेबल "मिनी क्यूब्स" शामिल होते हैं। इन मिनी क्यूब्स में जरूरी दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण होते हैं, जिन्हें आपदा या आपात स्थिति में तेजी से स्वास्थ्य-देखभाल सहायता पहुँचाने के लिए उपयोग किया जाता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:21:--

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए। इसका उद्देश्य 'प्रवासी भारतीय नागरिक' (OCI) कार्डधारकों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नाबालिगों के लिए पासपोर्ट नियमों को सख्त बनाना है।



मुख्य बिन्दु:

संशोधन के प्रमुख प्रावधान

- नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर प्रतिबंध: एक नया प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि कोई भी नाबालिग भारतीय पासपोर्ट रखने के साथ-साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण नहीं कर सकता है।
- e-OCI: अब OCI का दर्जा पारंपरिक फिजिकल कार्ड के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप (e-OCI) में भी जारी किया जा सकता है।

--:22:--

- **अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन:** पंजीकरण सहित सभी OCI प्रक्रियाएँ अब निर्धारित पोर्टल (ociservices.gov.in) के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी।
 - **डिजिटल माध्यम से OCI दर्जा त्याग करने की अनुमति:** यह प्रावधान OCI सुविधा के त्याग और रद्द करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसमें फिजिकल कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है और पूरी प्रक्रिया के लिए डिजिटल स्वीकृति भी दी जाती है।
 - **फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन (FTI) सहमति:** अब OCI आवेदक अपनी बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने की सहमति दे सकते हैं। इससे उनका फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम में स्वतः पंजीकरण हो जाता है।
 - **अपीलीय तंत्र:** OCI से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई अब मूल निर्णय लेने वाले प्राधिकरण से एक रैंक उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना**
- **परिचय:** इसे नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
 - 2015 में, भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड योजना का इसमें विलय कर दिया गया था।
- पात्रता:**
- जो व्यक्ति 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे।
 - **अपवाद:** वे लोग जो कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी अन्य देश के नागरिक रहे हैं, इसके लिए पात्र नहीं हैं।
 - यह कार्ड भारत में मतदान करने या संवैधानिक पद धारण करने जैसे राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है।
 - OCI एक अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेष सुविधा है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसका OCI दर्जा रद्द किया जा सकता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

व्हिटली पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- बरखा सुब्बा और परवीन शेख ने हिमालयन सैलामैंडर और इंडियन स्किमर के पर्यावासों की रक्षा करने के लिए व्हिटली पुरस्कार प्राप्त किए।



मुख्य बिन्दु:

व्हिटली पुरस्कार

- यह यूनाइटेड किंगडम स्थित एक प्रकृति संरक्षण चैरिटी, 'व्हिटली फंड फॉर नेचर' द्वारा प्रदान किया जाता है।
- उद्देश्य:** इसका उद्देश्य वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में संरक्षणवादियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- मान्यता:** इसे ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 02 May, 2026



हिमालयन सैलामैंडर

- यह पूर्वी हिमालय में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और अर्ध-जलीय उभयचर है।
- यह भारत, नेपाल और भूटान की स्थानिक प्रजाति है, तथा म्यांमार, थाईलैंड आदि में भी पाई जाती है।
- इसे IUCN द्वारा 'वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इंडियन स्किमर

- यह उन तीन पक्षी प्रजातियों में से एक है जो स्किमर जीनस (वंश) 'रिनचॉप्स' से संबंधित हैं।
- इसे IUCN द्वारा एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत इस प्रजाति की 90% से अधिक वैश्विक समष्टि का पर्यावास है, विशेष रूप से चंबल नदी में।

--:25:--